P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता : एक समाजशास्त्रीय समीक्षा

Rural Development and Farmer Dynamics: A Sociological Review

Paper Submission: 00/00/2020, Date of Acceptance: 00/00/2020, Date of Publication: 00/00/2020

रत्नेश कुमार
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र "ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता" में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय साहित्य की पुनर्परीक्षा पर आधारित है। इस शोधपत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि ग्रामीण विकास से कैसे कृषकों का जीवन गतिशील हुआ है। ग्रामीण विकास का कृषकों के पद,स्थिति, स्थान पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामो जैसे उन्नत कृषि,पशुपालन,पेयजल, दुग्ध डेयरी, कुटीर उद्योग, ग्रामीण सड़कें, बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास, मत्स्य पालन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि सुधार, डिजिटलीकरण आदि ने ग्रामीण जीवन में क्या भूमिका निभाई आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही कृषक राजनेता,व्यवसायी, बीमा एजेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग, मेकेनिक , प्रबंधनकर्ता,के रूप में कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। आदि का भी अध्ययन किया गया है।ग्रामीण विकास और गतिशीलता से कृषकों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या बदलाव हुए हैं। तथा उनके जीवन स्तर जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए हैं आदि से संबंधित सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है इसके साथ ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने कृषकों के जीवन में क्या बदलाव किए हैं। का भी अध्ययन समाहित हैं। इसके साथ ही ग्रामीण विकास करते समय पर्यावरण का कैसे ध्यान रखा जा रहा है। अर्थात कृषि के लिए कीटनाशक दवाइयों का निर्माण करते समय उन्हीं दवाइयों को प्राथमिकता दी जाती है जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं जिससे सतत विकास की अवधारणा चरितार्थ हो सके। का भी अध्ययन किया गया है।

The research paper presented is based on a review of some important sociological literature associated with "Rural Development and Farmer Mobility". In this paper it has been analyzed how the life of farmers has become dynamic due to rural development. What effect has rural development had on the position, status, location of farmers. In addition, various aspects of rural development such as advanced agriculture, animal husbandry, drinking water, dairy dairy, cottage industries, rural roads, infrastructure housing, fisheries, rural electrification, land reforms, digitization etc. played a role in rural life etc. Has also been highlighted. Along with this, how farmers are leading as politicians, businessmen, insurance agents, property dealing, mechanics, managers. Adi has also been studied. What are the social, economic, political changes in the lives of farmers due to rural development and mobility. And all aspects related to their standard of living, what changes have been made in the lifestyle etc. have been analyzed, as well as what changes have been made in the lives of farmers by rural development programs. Study of Along with this, how environment is being taken care of while doing rural development. That is, while manufacturing pesticides for agriculture, priority is given to those medicines which are environmentally friendly so that the concept of sustainable development can be realized. Has also been studied.

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, कृषक गतिशीलता, सतत विकास।
Rural Development, Farmer Mobility, Sustainable Development.

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसमें ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास पर बल दिया जाता है। इसमें कृषि और सहायक गतिविधियों जैसे ग्रामीण और एवं कुटीर उद्योग, शिल्पकारी, सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना सामुदायिक सेवाएं एवम सुविधाएं और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनो का विकास सम्मिलित हैं।(कटार सिंह 2018)। टोड़ेरो(1995) ने ग्रामीण विकास की

तीन बुनियादी तत्व बताएं, 1 जीवन की आधारभूतआवश्यकता जिसमें रोटी कपड़ा मकान के साथ–साथ शिक्षा स्वास्थ्य, चिकित्सा, जीवन संपदा रक्षा को भी सम्मिलित किया जाता है 2आत्मसम्मान प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र का अपना आत्मसम्मान एवम गरिमा होता है 3 स्वतंत्रता– स्वतंत्रता का आशय राजनीतिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक दासता से मुक्ति से है। जब तक एक समाज व्यक्ति, प्रकृति ,अनभिज्ञता एवं अन्य व्यक्तियों संस्थाओं एवं कट्टर मान्यता की दासता से बंधा है वह विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। दासता का कोई भी स्वरूप अपर्याप्त विकास की स्थिति का घोतक है।

कृषक गतिशीलता

कृषक गतिशीलता का तात्पर्य कृषकों के पद, स्थिति, स्थान में परिवर्तन से है। आंद्रे बेते ने कृषक की तीन अर्थ बताएं 1 कृषक भूमि से जुड़ा होता है। वह न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम द्वारा लाभदायक बनाता है अपनी आजीविका श्रम द्वारा कमाता है। 2 कृषक समाज की समाज में निम्न स्थिति होती है जो केवल भूमि से अपनी आजीविका कमाता है उसके आय बहुत कम होती है। 3 कृषक समाज को मजदूरों का पूरक माना जाता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषक एवं श्रमिको को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। (आन्द्रेबेते 1974) । रेडफिल्ड (1965) ने कृषक वर्ग के अंतर्गत छोटे वर्ग खेतिहर उत्पादन कर्ताओं को सम्मिलित किया है। जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। उन लोगों को किसान कहा जाता है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। रेड फील्ड ने कृषक समाज की पांच विशेषताओं को बताया है। 1 कृषक समाज समरूप समाज होता है। 2 कृषक समाज की आजीविका का मुख्य साधन भूमि होता है।3 कृषक समाज अविभेदीकृत और अस्तरीकृत समुदाय है।4 कृषक समाज नगरों अथवा कस्बों के कुलीन वर्ग से भी नहीं है। यद्यपि उनसे अनेक क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं 5 कृषक समाज को आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से अस्पष्टता पृथक किया जा सकता है। थियोडोर सनीन(1971) में कृषक समाज की दो विशेषताएं बताई हैं 1 कृषक समाज खेत को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई मानता है। 2 भूमि आजीविका का प्रमुख साधन है।

इस प्रकार जब कृषक को अनेक योजनाओं का लाभ मिला तो उनके जीवन में गतिशीलता आईं और वह कृषक से किसान में परिवर्तित हो गए ।

पद्धतिशास्त्र

इस पेपर में ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता से संबंधित द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। जिसमें पुस्तकों,शैक्षणिक पत्रिकाओं ,शोध आलेखों में प्रकाशित लेख की समीक्षा शामिल हैं।इस पत्र में ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया हैं।

साहित्य समीक्षा

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी इस व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आधार पर किया गया था इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास को अधिक गति देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर 1992 में पारित हुआ जिसमें पंचायतों के विकास के लिए 29 कार्य बताए गए जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, सिंचाई, भूमि संरक्षण, भूमि सुधार, पेयजल, मार्गो का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा ,प्रौढशिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत,आंगनबाड़ी, वृद्धावस्था पेंशन, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, परिवार कल्याण, जन्म मृत्यू, विवाह का पंजीकरण आदि (गुरनाम सिंह 2014)

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं कृषक गतिशीलता

ज्या द्रेज(2017) ने लोकतंत्र और भोजन का अधिकार लेख में बताया कि यह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का एक रूप है। भारत ने अल्प पोषण की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं संचालित की हैं,जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना ,खाद्य सुरक्षा ,गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन जैसी अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। जिससे लोगों के भोजन के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो रही है।

मिहिर शाह (2017) रोजगार गारंटी नागरिक समाज और भारतीय लोकतंत्र लेख में बताया की रोजगार गारंटी मनरेगा ग्रामीण भारत में गरीब एवं वंचित वर्ग जो संकट का सामना कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। नागरिक समाज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके 6 परिणाम प्रमुख हैं जो संकट के समय राहत के साथ–साथ भारतीय खेती में सूखा एवं बाढ़ रोकने की दिशा में दीर्घकालिक कदम साबित हो रहे हैं इसमें जहां एक ओर ग्रामीण समाज में सतत संवृद्धि दर आगे बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर गरीबी में कटौती होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी खेती में सुधार होगा सतत जीविका श्रेणी निर्मित करने में सहायक होगी। इसके साथ ही निजी निवेश में द्वितीयक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

सलोनी चोपड़ा और पुडुचेरी जेसिका (2017) भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक अवलोकन योजना का मूल्यांकन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं शामिल हैं जिसमे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ,अन्नपूर्णा योजना आदि जिसमें

उन्होंने बताया की एन.एस. ए. पी कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा समय में 2.6 करोड़ बुजुर्गों विकलांगों और विधवाओं के जीवन में स्थायित्व लाने के लिए उनके जीवन में कल्याणकारी साबित हुई है।

सुरेंद्र जोधका और कमल नयन चौबे 2019 ने ग्रामीण जीवन के विविध आयामों का अध्ययन किया और बताया कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन गत्यात्मक परिवर्तनशील तक की तस्वीर प्रस्तुत करता है। जिसमें उन्होंने बताया की भारतीय गांव की स्थिति एवम् जातियों की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। सरकारी नीतियों के कारण भारतीय गांव की दिशा और दशा में सुधार हो रहा है। ग्रामीण परिवेश का आधुनिक और शैक्षिक दृष्टिकोण ग्रामीण राजनीति तथा कृषि संबंधी परिवर्तन सुखद परिणामों के रूप में लोगो के सामने आ रहे है। जिससे ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

कटार सिंह और अनिल सिसोदिया (2016) ने ग्रामीण समाज में वित्त पोषण लेख में बताया कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत पूंजी की आवश्यकता होती थी। उन्होंने ग्रामीण विकास परियोजना में निवेश के लिए वित्त के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया घरेलू ,विदेशी। जिसके अंतर्गत सरकारी बैंक रिजर्व बैंक नाबार्ड कंपनियां विश्व बैंक आदि ने ग्रामों की विकास एवं रोजगार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है जिससे ग्रामों का कायाकल्प हो रहा है। ग्रामों में अनेक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण लोग खेती के साथ साथ अपना बिजनेस स्वयं स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप उनमें व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ रही है। ग्रामीण सड़कों के किनारे या चौराहों पर अनेक दुकानें एवं छोटे उद्योग इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि किसान बिजनेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

जॉर्ज शांति (2019) दुग्ध क्रांति और ग्रामीण भारत के लेख में बताया कि दुग्ध क्रांति से ग्रामीण भारत में जहां एक ओर उन्नत गाय भैंस का प्रचलन बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन भी बढ़ रहा है दुग्ध क्रांति से दूध का प्रवाह गांव से शहर की तरफ जाने में हो रहा है जिससे शहरों का पैसा ग्रामों में आ रहा है वहीं दूसरी ओर ग्रामों में रोजगार सृजन हो रहा है ग्रामीण लोग अनेक मिठाइयों की दुकानों तथा दूध से निर्मित सामानों से अच्छी आय कमा रहे हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समाज में गरीबी उन्मूलन हुआ है।

ए.आर.देसाई (2016) ने सामुदायिक विकास योजनाःएक समाजशास्त्रीय विश्लेषण मैं योजना का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन किया और बताया की योजना संघात्मक सरकार द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण समाज के पुनर्गठन हेतु प्रारंभ की गई थी यह तीन चरणों में विभक्त थी राष्ट्रीय विस्तार चरण गहन सामुदायिक विकास चरण और गहन विकास उत्तर चरण इस योजना में आठ प्रकार के कार्य संबंध थे कृषि संदेश वाहन शिक्षा स्वास्थ्य प्रशिक्षण समाज कल्याण पूरक रोजगार और मकान मूल्यांकन समिति द्वारा जब इसका विश्लेषण किया गया तो इसमें अनेक कमियां सामने आई जिससे इसका नौकरशाही शुरू निर्णयों का ऊपर लिया जाना और नीचे प्रशासनिक ढंग से भेजना इसकी यंत्र प्रणाली में हर स्तर पर निर्वाचन सिद्धांतों का अभाव कर्मचारी वर्गों में श्रेष्ठ एवं अधीनता के संबंधों में अत्यधिक अव्यवस्था और संघर्ष का उद्भव समाज सेवा भाव में कमी इस प्रकार यह योजना अपने उद्देश्यों में असफल साबित हुई।

कटार सिंह और अनिल सिसोदिया ने (2016)अपने लेख गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम में बताया कि भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं। और इन लक्षित कार्यक्रमों कार्यक्रमों को चार भागों में बांटा गया है a गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जैसे मनरेगा c सार्वजनिक वितरण प्रणाली d समाज कल्याण उन्मुख कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना आदि इन सभी कार्यक्रमों से गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन हुआ है लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है ।उनमें आत्म निर्भरता बढ़ी है।

स्वामीनाथन ने (1996) सतत कृषि खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी सुरक्षा का अध्ययन कर बताया की खाद्य सुरक्षा जो कि सतत कृषि पर निर्भर करती है सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। और उसके बदले में सतत विकास के अभिन्न अंग का गठन करती हैं जिसके माध्यम से लोग खाद्यान्न सुरक्षा, संतुलित भोजन, सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षित भौतिक एवम् आर्थिक पहुंच के लक्ष्यार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है।

सुरजीत देव 2019 अपने लेख भारत में सामाजिक वर्ग ग्रामीण धन और समृद्धि में राज्य स्तरीय डेटा के आधार पर कहते हैं कि समाज में मध्यम वर्ग माध्यम और उच्च ग्रामीण सामाजिक वर्ग में अंतर पाया जाता है। ग्रामीण आजीविका पूरी तरह किस पर निर्भर नहीं है हालांकि ग्रामीण भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण उत्पादक सम्पत्ति माना जाता है इसलिए इसका वितरण कई राज्यों ने कम हो गया है सामाजिक परिवर्तन धन और समृद्धि पर केंद्रित है तेजी से शहरीकरण शहरों का विस्तार और कुछ मामलों में ग्रामीण धन सजन के लिए बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र उनकी आय के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहे हैं।

नीलाद्री भट्टाचार्य 2019 अपने लेख महान कृषि विजय पर औपनिवेशिक काल में ग्रामीण भारत का चित्रण करते हैं जिसमें कृषि खानाबदोश कारीगर आदि सम्मिलित हैं वह कृषि को समाज में परिवर्तन का प्रमुख स्रोत मानते हैं। और साथ ही परिवर्तन में संबंध होने में खोज भी करते हैं महान कृषि विजय प्रतिमान पुनरपरिभाषित कार्य है जो कृषि इतिहास में शोधकर्ताओं को उन श्रेणियों पर पर विचार करने के लिए मजबूर करता है।

अध्ययन की सीमाएं

यह शोध पत्र ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता पर आधारित हैं। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है। कि ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों से कैसे कृषकों का जीवन गतिशील हुआ है। यह शोध पत्र

अनेक पुस्तकों की समीक्षा एवं शोध आलेखों के आधार पर लिखा गया है इसलिए अंशतः सत्य कहा जा सकता है। लेकिन इसके निष्कर्षों को सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र ग्रामीण विकास और कृषक गतिशीलता के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालता है। इस शोधपत्र में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न आयामों जैसे कृषि, पशुपालन, डेरी, उन्नत सड़कें, भूमि सुधार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। वैसे ही कृषकों के जीवन में गतिशीलता आयी हैं। जिसके कारण उनके पद, स्थिति, स्थान में परिवर्तन हुआ है उनका जीवन स्तर आधुनिक मानदंडों की जीवन शैली के अनुरूप विकसित हुआ है उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही शोध पत्र में यह भी पाया गया कि किसानों के आय के स्रोतों में विविधता आयी हैं। और वह कृषि के साथ गैर खेतिहर व्यवसाय भी अपना रहे हैं। वर्तमान समय में किसान राजनेता व्यवसाय, बीमा एजेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग, मकैनिक, प्रबधनकर्ता आदि के रूप भूमिका निभाना उनके सशक्त होने का प्रमाण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *टी, शैनिन. 1987. पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी. लन्दन : ब्लैकवेल .*
2. *आन्द्रेबेते. 1974. सिक्स एसेज इन कम्पेरेटिव सोशियोलॉजी न्यूयार्कः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस .*
3. *रेडफील्ड, आर.1965. पीजेंट सोसाइटी एड कल्चर . शिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस*
4. *सिंह ,गुरुनाम.2014. पंचायतीराज. लखनऊः शिवम् प्रिंटर्स.*
5. *भट्टाचार्य, निलादी .2019. "महान कृषि विजय" . कॉन्ट्रिब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी. .अक्टूबर 19 वॉल्यूम 53 नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन.*
6. *देव,सुरजीत .2019. "भारत में सामाजिक वर्ग ग्रामीण धन और सम्रद्धि" .सोशल चेंज जर्नल ऑफ द काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट. दिसम्बर 19.वॉल्यूम 49. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन.*
7. *ज्या, द्रेज (संपादित).2017. "लोकतंत्र और भोजन का अधिकार" संकलित भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष ,.नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.*
8. *शाह, मिहिर,2017. "रोजगार गारंटी नागरिक समाज और भारतीय लोकतंत्र" इन ज्या द्रेज (संपादित) "भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष", नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन.*
9. *चोपड़ा, सलोनी और पुडुसेरी जेसिका. 2017. "भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन : एक अवलोकन" इन ज्या द्रेज (संपादित) भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष , नई दिल्ली :वाणी प्रकाशन.*
10. *जोधका, सुरेंद्र एस और कमल नयन चौबे,2019. ग्रामीण परिवेश का बदलता जीवन :सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य , नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन.*
11. *देसाई, ए.आर. 2016. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र ,जयपुर :रावत पब्लिकेशन.*
12. *सिंह, कटार और अनिल सिसोदिया (संपादित),2016. "ग्रामीण विकास का वित्तपोषण" संकलित ग्रामीण विकासः सिद्धांत नीतियां प्रबंधन , नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन .*
13. *जॉर्ज, शांति ,2019. "दुग्ध क्रांति और ग्रामीण भारत" इन सुरेंद्र जोधका (संपादित) ग्रामीण विकासः परिप्रेक्ष्य नीतियां कार्यक्रम ,नई दिल्ली :वाणी पब्लिकेशन.*
14. *स्वामीनाथन ,एमएस.,''साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी" , इंडियन जनरल आफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ,51 ,2:60–75, 1996.*
15. *टोडेरो, मिचेल.1995. इकोनामिक डेवलपमेंट ,फिफ्थ एडिशन न्यूयार्क एंड लंदन : लाग मैन.*